अर्थ-व्यवस्था में तम्बाकू-उत्पादकों का योगदान

120. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू-उत्पादकों का अर्थ-व्यवस्था में क्या योगदान है;

(ख) इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) क्या सरकार तम्बाकू की खेती पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तम्बाकू उत्पादक विभिन्न प्रकार से मुख्यतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद, रोजगार सृजन, उत्पाद शुल्क, राजस्व तथा विदेशी मुद्रा अर्जन के माध्यम से देश की अर्थ-व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं।

(ख) तम्बाकू का रकबा बढ़ाने के लिए अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, वाणिज्य मंत्रालय का तम्बाकू बोर्ड देश में वर्जिनिया तम्बाकू की उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

तम्बाकू के निर्यात में वृद्धि हेतु तम्बाकू बोर्ड विभिन्न उपाय कर रहा है—जैसे—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्षमता वाले नए बाजारों सहित विभिन्न देशों में व्यापार शिष्ट मंडलों के नियमित दौरे, अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी निर्धारण प्रणाली को सरल बनाना, प्रचार आदि।

(ग) जी, नहीं।

भारत में कृषि उत्पादन

121. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रति हैक्टर—कृषि उत्पादन विश्व उत्पादन की तुलना में कम है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार अनेक केन्द्रीय क्षेत्रक/केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। कार्यान्वित की जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं—(1) एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम (2) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं (3) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—मक्का तथा कदन्न (4) गहन कपास विकास कार्यक्रम तथा (5) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम। क्रम सं० (2), (3) तथा (5) में उल्लिखित योजनाएं भारत सरकार द्वारा शत्प्रतिशत वित्तपोषित हैं। अन्य योजनाएं साझा आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं में प्रमाणीकृत बीजों, खरपतवार नाशियों तथा पौध रक्षण रसायनों के उपयोग के लिए कृषकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है। सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से नियत समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।

Research in Wheat Crop

122. **DR. NAUNIHAL SINGH** : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the research efforts in wheat crop are holding out the promise of sustaining the green revolution so as to make possible production in the vicinity of 75 million tonnes by the end of this decade; if so, the details thereof;

(b) whether it is also a fact that once again resource crisis, that has derailed many projects in the past, may prove a stumbling block; if so, the details thereof; and

(c) the steps Government have taken or propose to take to ward off such on eventuality ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir, this will be achieved through adoption of appropriate production and protection technologies relevant to various cropping systems.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise

Functioning of farm Universities in the Country

123. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of farm universities in the country and what are the details of annual State expenditure on them besides the funds from the ICAR for financing various research projects ;

(b) whether it is a fact that the audit report of the Comptroller and Auditor General (CAG) has revealed serious lapses in the functioning of several universities and the IARI (New Delhi), in respect of ineffective monitoring of programmes and involving a lot of wasteful expenditure; if so, the details thereof; and

(c) what steps Government have taken to solve the problems indicated by the CAG ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) to (c) The information is being collected and will be laid down on the table of the Sabha in due course.

Arrears of dues Payable to Sugarcane Growers in Uttar Pradesh

124. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that high prices of sugarcane as advised by states had let to build up of arrears of dues and discouraged farmers from growing sugarcane;

(b) if so, what steps Government have taken to cope up with the situation;

(c) the amount of arrears still outstanding as on July, 1993, especially amount of arrears due against Uttar Pradesh; and

(d) the action being taken by Government to help settle such dues with details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir. It is a fact that high State Advised Prices of sugarcane give rise to incidence of arrears. Mounting of arrears also affect the liquidity of the industry. Delay in payment of cane price dues may prompt the farmers to switch over to other remunerative crops.

(b) to (d) To improve the economic viability of the sugar factories and to liquidate the cane price arrears the Government has taken the following measures:

(i) The Statutory Minimum Price (SMP) of sugarcane for 1992-93 season was raised from Rs. 27 per quintal to Rs. 31 per quintal. The SMP for 1993-94 season has been fixed at Rs. 34.50 per quintal. An advance announcement for 1994-95 season has also been made at the rate of Rs. 37.00 per quintal.

(ii) Levy to free sale ratio was changed from 45 : 55 to 40 : 60 in February, 1993.

(iii) The release mechanism has been regulated in such a manner so as to ensure adequate realisation to the sugar factories.

(iv) Special releases have been allowed to sugar factories which were having high cane price arrears.